<u>लोक सभा</u>

अतारांकित प्रश्न संख्या 3699

19 मार्च, 2018 को उत्तर के लिए

इस्पात विनिर्माता

3699. श्री रवनीत सिंहः

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में इस्पात विनिर्माण की प्रभावकारिता का मूल्यांकन करने के लिए कोई संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन शुरू किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार इस बात में विश्वास करती है कि इस क्षेत्र में व्यवसाय की सहायता के लिए इस्पात उद्योग में भारी आधारभूत ढांचा पुनर्विकास करने की आवश्यकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने लागत सक्षमता में सुधार के लिए इस्पात पुनर्चक्रण में निवेश की आवश्यकता का मूल्यांकन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पंजाब राज्य में इसकी क्या संभावना है?

<u>उत्तर</u>

इस्पात राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय)

(क): जी नहीं।

(ख): जी हाँ। राष्ट्रीय इस्पात नीति (एनएसपी), 2017 में वर्ष 2030-31 तक 300 एमटी की क्रूड इस्पात क्षमता की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है, जिसके लिए प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों, वित्त, जनशक्ति और भूमि सहित अवसंरचनाओं की आवश्यकता है।

(ग): एनएसपी, 2017 के अनुसार, विद्युत फर्नेस से इस्पात उत्पादन, जो कि स्क्रैप और रिसाइकल्ड इस्पात के प्रमुख उपयोगकर्ता हैं, द्वारा वर्ष 2030-31 तक लगभग 35-40% योगदान की परिकल्पना की गई है। इस्पात स्क्रैप की रिसाइकलिंग से उपलब्धता बढ़ेगी और भारत में इस्पात उत्पादन में लागत मितव्ययता में सुधार होगा। एनएसपी, 2017 में इस पर उचित विचार किया गया है।

पंजाब राज्य में निवेश संबंधी जानकारी उपलब्ध नहीं है।

******